



नकद अंतरण से निर्णय-अधिकार तक : मध्य प्रदेश की लाइली बहना योजना का महिला एजेंसी, वित्तीय समावेशन और सामाजिक-आर्थिक स्वायत्तता पर प्रभाव

दशरथ प्रसाद अहिरवार

शोधार्थी विषय अर्थशास्त्र महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर (म प्र)

विनीता अहिरवार

शोधार्थी विषय अर्थशास्त्र सहायक प्राध्यापक जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर (म प्र)

डॉ पदम् नारायण

सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र शासकीय महाविद्यालय पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी (म प्र)

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.21470292>

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Received: 12-05-2026

Accepted: 29-06-2026

Published: 15-07-2026

Keywords:

लाइली बहना योजना, महिला एजेंसी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, वित्तीय समावेशन, सामाजिक-आर्थिक स्वायत्तता, घरेलू निर्णय-अधिकार, मध्य प्रदेश

ABSTRACT

मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना भारतीय राज्यों में बढ़ती नीति-प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें महिलाओं को निर्णय-अधिकार, पारिवारिक संसाधनों और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के लिए प्रत्यक्ष नकद अंतरण किया जाता है। योजना की आधिकारिक योजना के अनुसार, योग्य महिलाओं को उनकी योग्यता अवधि में प्रति माह 1500 रुपये डीबीटी-सक्रिय बैंक खाते में दिए जाते हैं (Madhya Pradesh Government, nd-a). ऐसा किया जाता है ताकि लाभ सीधे महिला के खाते में पहुंचे और परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका मजबूत हो सके। यह अध्ययन नकद अंतरण को केवल आय-सहायता के रूप में नहीं देखता, बल्कि महिला संस्थाओं, वित्तीय समावेशन और सामाजिक-आर्थिक स्वायत्तता के मध्य स्थित एक बहुआयामी नीति-उपकरण के रूप में देखता है। शोध-पत्र में NFHS-5, वैश्विक वित्तीय समावेशन लेख, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण संबंधी सरकारी स्रोतों, महिला-केंद्रित नकद अंतरण और उपलब्ध आधिकारिक योजना-दस्तावेजों की समीक्षा की

Disclaimer: The opinions, interpretations, conclusions, recommendations, analyses, and statements expressed in this research article are solely those of the author(s) and do not reflect the views, policies, or positions of the Publisher, Chief Editor, Editors, Editorial Board, Reviewers, or their affiliated institutions. The author(s) are solely responsible for ensuring the originality, authenticity, and integrity of the manuscript and for ensuring that it is free from plagiarism, AI-generated content, copyright infringement, data falsification, and any other form of academic misconduct.

गई है। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि बैंक खाते में सीधा भुगतान महिलाओं की दृश्य आर्थिक उपस्थिति को बढ़ाता है, लेकिन असली स्वायत्तता तभी आती है जब महिला खाते का उपयोग स्वयं कर सके, खर्चों और निकासी पर नियंत्रण रख सके, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता प्राप्त करे और घरेलू सामाजिक मानदंड उसके निर्णय-अधिकार को स्वीकार करें। उदाहरणात्मक सांख्यिकीय विश्लेषण बताता है कि महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्वायत्तता बैंक खाते पर नियंत्रण, अंतरण की नियमितता, शिक्षा, पारिवारिक समर्थन और डिजिटल साक्षरता से सकारात्मक रूप से जुड़ी हो सकती है। शोध-पत्र ने पाया कि लाइली बहना योजना का सशक्तिकरण-प्रभाव वित्तीय क्षमता, स्थानीय सेवा प्रणाली, लैंगिक मानदंडों और पूरक आजीविका अवसरों पर निर्भर करता है, न कि पैसे की मात्रा।

1. भूमिका

1.1 नकद अंतरण और लैंगिक नीति-परिप्रेक्ष्य

भारतीय कल्याणकारी राज्यों में नकद अंतरण योजनाएँ अब सिर्फ गरीबी को दूर करने का तकनीकी उपाय नहीं हैं; वे अब घरेलू सत्ता-संतुलन, लैंगिक न्याय, नागरिकता और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी राजनीतिक बहसों का केंद्र बन चुकी हैं। विशेष रूप से महिलाओं को लक्षित नकद अंतरण मानकर तैयार किए जाते हैं कि घरेलू उपभोग, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य-व्यय, बचत और आत्मसम्मान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। महिला के खाते में पैसा जमा होना और उस पैसे पर असली नियंत्रण हासिल करना दो अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं। इस शोध-पत्र का मुख्य बौद्धिक आधार इस अंतर को समझना है।

1.2 लाइली बहना योजना का शोध-संदर्भ

मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की लाइली बहना योजना भी इसी संदर्भ में विचार की जानी चाहिए। योजना का घोषित लक्ष्य है कि महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन-क्षमता, स्वास्थ्य-पोषण स्थिति और परिवार में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाई जाए। ताकि धन सीधे महिला तक पहुंचे, भुगतान आधार-लिंक और DBT-सक्रिय स्वयं के बैंक खाते में किया जाता है (Central Government, n.d.-a)। यह योजना महिला संस्थाओं और वित्तीय समावेशन के बीच एक स्पष्ट नीति संबंध बनाती है।

1.3 आय-प्राप्ति और वास्तविक सशक्तिकरण का अंतर

फिर भी आय-प्राप्ति सशक्तिकरण का मात्रांक नहीं है। अमर्त्य सेन की क्षमता दृष्टिकोण के अनुसार, विकास का असली अर्थ है कि व्यक्ति अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय ले सके और उन पर अमल कर सके (Sen, 1999)। महिला एजेंसी चुनाव की क्षमता, संसाधनों पर नियंत्रण और सामाजिक स्वीकृति से बनती है। वित्तीय समावेशन का सांख्यिकीय संकेत वास्तविक स्वायत्तता में परिवर्तित नहीं होता अगर महिला बैंक खाते की धारक है, लेकिन निकासी पति या परिवार का कोई सदस्य इसे चलाता है।

1.4 मध्य प्रदेश में महिला वित्तीय समावेशन की स्थिति

NFHS-5 के मध्य प्रदेश संबंधी संकेतक बताते हैं कि राज्य में महिलाओं की बैंकिंग उपस्थिति में काफी वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में 74.7 प्रतिशत महिलाओं ने स्वयं का बैंक या बचत खाता था, जो NFHS-4 के 37.3 प्रतिशत से अधिक है (IIPS & ICF, 2021)। इसी तरह, विवाहित महिलाओं में घरेलू निर्णयों में भागीदारी का कुल स्तर 86.0 प्रतिशत था, लेकिन उनमें से 38.5 प्रतिशत ने मोबाइल फोन का स्वयं उपयोग किया था। ये आंकड़े दिखाते हैं कि खाते की उपलब्धता और डिजिटल और सूचनात्मक स्वायत्तता का अंतर अभी भी है।

1.5 अध्ययन का विश्लेषणात्मक फोकस

इस शोध-पत्र में लाइली बहना योजना का विश्लेषण तीन प्रमुख आयामों पर किया गया है: महिला एजेंसी, वित्तीय समावेशन और सामाजिक-आर्थिक स्वायत्तता। शोध-पत्र का कहना है कि नकद अंतरण महिला को निर्णय-अधिकार दे सकता है, लेकिन यह स्वयं पूर्ण नहीं होता। इसके लिए स्थानीय प्रशासनिक सुगमता, वित्तीय साक्षरता, सामाजिक समर्थन, पारिवारिक सत्ता-संतुलन और बैंकिंग प्रणाली महत्वपूर्ण हैं।

2. लाइली बहना योजना की पृष्ठभूमि और नीति-संदर्भ

2.1 योजना का स्वरूप और उद्देश्य

मध्य प्रदेश शासन द्वारा शुरू की गई राज्य-स्तरीय सामाजिक सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका को बढ़ाना है। आधिकारिक योजना-पृष्ठ के अनुसार योग्य महिलाओं की आयु 21 वर्ष से 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए; वे विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता नहीं होनी चाहिए (Madhya Pradesh Government, nd-a)। वर्तमान आधिकारिक विवरण के अनुसार, प्रत्येक योग्य महिला को प्रति माह 1500 रुपये डीबीटी-सक्रिय बैंक खाते में भुगतान करना होगा।

2.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और JAM ढाँचा

योजना का निर्माण प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली से जुड़ा हुआ है। DBT का मूल उद्देश्य लाभों को अधिक पारदर्शी, त्वरित और उत्तरदायी तरीके से लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचाना है। DBT का मुख्य सक्षमकारी ढाँचा भारत में जन-धन, आधार और मोबाइल (JAM) है, जो पहचान, खाता और संचार को जोड़कर कल्याणकारी वितरण को डिजिटल बनाता है (Direct Benefit Transfer Mission, n.d.)। लाइली बहना योजना राज्य-स्तरीय वितरण-तर्क का महिला-केंद्रित संस्करण है।

2.3 व्यक्तिगत बैंक खाते की अनिवार्यता

नीति की दृष्टि से, योजना में महिला के “स्वयं के खाते” पर विशेष नियंत्रण है। आधिकारिक प्रश्नोत्तर (FAQ) के अनुसार, संयुक्त खाता मान्य नहीं है और आवेदिका का स्वयं का नाम और डीबीटी-सक्रिय बैंक खाता आवश्यक है (Central Government, n.d.-b)। यह शर्त सिर्फ प्रशासनिक नियम है; यह भी लाभ के वास्तविक नियंत्रणकर्ता और नाममात्र प्राप्तकर्ता के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास है।

2.4 निर्णय-अधिकार और वित्तीय समावेशन का नीति-संबंध

योजना के आधिकारिक उद्देश्य में स्पष्ट रूप से यह विचार है कि महिला को धन मिलने से परिवार की आवश्यकताओं पर खर्च करने की स्वतंत्रता मिल सकती है और घरेलू निर्णयों में उसकी भूमिका बढ़ सकती है (Central Government, nd-a)। नकद अंतरण, बैंकिंग समावेशन और महिला संस्थाएं यहाँ एक दूसरे से जुड़ते हैं। फिर भी, इस संबंध की व्यावहारिक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि महिला अपने खाते तक भौतिक रूप से पहुँच सकती है या नहीं, क्या बैंकों और कियोस्क सेवाओं की सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्या परिवार धन पर नियंत्रण रखता है और क्या महिला डिजिटल और वित्तीय प्रक्रियाओं को समझती है।

2.5 मध्य प्रदेश की सामाजिक-आर्थिक प्रासंगिकता

इस योजना को मध्य प्रदेश में सामाजिक-आर्थिक विषमता, ग्रामीण-शहरी विभाजन, आदिवासी और पिछड़े वर्गों की उपस्थिति और महिला श्रम-भागीदारी की चुनौतियों ने और अधिक प्रासंगिक बना दिया है। NFHS-5 अवधि में मध्य प्रदेश में बहुआयामी गरीबों का अनुपात 20.63 प्रतिशत था (UNDP India, 2023)। NITI Aayog, 2023 में इस तरह की परिस्थितियों में, नियमित नकद हस्तांतरण को घरेलू खपत-सुरक्षा और महिलाओं की आर्थिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

तालिका 1: मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण से जुड़े चयनित NFHS संकेतक

संकेतक	शहरी	ग्रामीण	कुल NFHS-5	कुल NFHS-4
विवाहित महिलाएँ जो सामान्यतः तीन घरेलू निर्णयों में भाग लेती हैं (%)	91.7	84.1	86.0	82.8
पिछले 12 महीनों में काम करने और नकद भुगतान पाने वाली महिलाएँ (%)	23.2	28.0	26.8	29.9
घर/भूमि पर अकेले या संयुक्त स्वामित्व वाली महिलाएँ (%)	35.8	41.3	39.9	43.5
बैंक/बचत खाता जिसका महिला स्वयं उपयोग करती है (%)	78.5	73.3	74.7	37.3
मोबाइल फोन जिसका महिला स्वयं उपयोग करती है (%)	58.8	31.4	38.5	28.7

स्रोत: NFHS-5 मध्य प्रदेश राज्य तथ्य-पत्र/राष्ट्रीय रिपोर्ट में प्रकाशित चयनित संकेतक (IIPS & ICF, 2021)।

3. साहित्य समीक्षा

3.1 महिला-केंद्रित नकद अंतरण की अवधारणा

महिला-केंद्रित नकद अंतरण पर उपलब्ध लेखों में सहमत है कि धन का प्राप्तकर्ता कौन है, भुगतान किस माध्यम से आता है और प्राप्तकर्ता का सामाजिक स्थान नीति-परिणामों को प्रभावित करता है। नकद अंतरण उपभोग-सुरक्षा को बढ़ा सकता है, लेकिन महिला सशक्तिकरण का असर तभी दिखाई देता है जब वे अपने संसाधन पर नियंत्रण पाते हैं और घरेलू निर्णयों में अपनी आवाज़ को सुनते हैं।

3.2 बैंक खाते, प्रशिक्षण और वित्तीय नियंत्रण पर साक्ष्य

Field और सहलेखकों (2021) ने भारत में एक प्रयोगात्मक अध्ययन में पाया कि महिलाओं के स्वयं के बैंक खाते, खाते का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण, सार्वजनिक क्षेत्र की मजदूरी का सीधे खाते में भुगतान, महिलाओं के श्रम-आपूर्ति व्यवहार और लैंगिक मानदंडों को प्रभावित कर सकते हैं। यह अध्ययन बताता है कि एकमात्र बैंक खाता पर्याप्त नहीं है; खाता सक्रिय उपयोग, प्रशिक्षण और आय-नियंत्रण से जुड़ना चाहिए। इस निष्कर्ष का लाइली बहना योजना से सीधा संबंध है क्योंकि भुगतान एक महिला के DBT-सक्रिय व्यक्तिगत खाते में किया जाता है।

3.3 नकद अंतरण और घरेलू निर्णय-प्रक्रिया

Somville, Almås और Vandewalle (2020) ने भारत के ग्रामीण संदर्भ में दिखाया कि जब एक महिला नकद अंतरण प्राप्त करती है, तो उसकी भागीदारी घरेलू निर्णयों में बढ़ सकती है, हालांकि आय, व्यय या बचत के सभी परिणाम स्वतः नहीं बदलते। यह कहते हुए कि नकद अंतरण महिला-केंद्रित “निर्णय-भूमिका” को बदल सकता है, लेकिन आर्थिक संरचना में व्यापक परिवर्तन के लिए पूर्ण उपाय आवश्यक हैं।

3.4 डिजिटल भुगतान और संरक्षणात्मक कार्यक्रम-डिज़ाइन

Center for Financial Inclusion and World Food Programme (2023) ने कहा कि प्रत्यक्ष डिजिटल भुगतान महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, गोपनीयता और धन पर नियंत्रण दे सकता है, लेकिन कार्यक्रम डिज़ाइन में मोबाइल उपलब्धता, KYC, डिजिटल वित्तीय साक्षरता, शिकायतों का समाधान और निकासी-बिंदुओं की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। यह चेतावनी भारत के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विशेष महत्वपूर्ण है, जहाँ डिजिटल साक्षरता और बैंकिंग संपर्क-बिंदु समान रूप से उपलब्ध हैं।

3.5 वैश्विक वित्तीय समावेशन और लैंगिक डिजिटल अंतर

Global Findex 2021 के भारत संबंधी देश-पत्र से पता चलता है कि भारत ने खाता-स्वामित्व में काफी वृद्धि की है, लेकिन लिंग और शहरी-ग्रामीण डिजिटल भुगतान उपयोग में अभी भी अंतर है। 2021 में भारत में 35 प्रतिशत वयस्कों ने डिजिटल भुगतान किया या प्राप्त किया था (Klapper, 2022), और महिलाओं की संभावना पुरुषों से 13 प्रतिशत कम थी। यह स्पष्ट है कि खाते की संख्या से नहीं, बल्कि डिजिटल भुगतान, बचत, ऋण और वित्तीय आत्मविश्वास से वित्तीय समावेशन को मापना चाहिए।

3.6 भारत में DBT और तकनीकी वितरण प्रणाली

भारत में पारदर्शिता और लक्षित वितरण के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण महत्वपूर्ण है। DBT मिशन के अनुसार, JAM ढाँचा लाभों को सीधे बैंक खातों में पहुंचाने की व्यवस्था करता है (Direct Benefit Transfer Mission, n.d.)। लेकिन कल्याणकारी तकनीक सफल होने के लिए सामाजिक संरचनाओं की जरूरत है। DBT के माध्यम से आया धन भी महिला एजेंसी में पूरी तरह से बदल नहीं पाता अगर परिवार या स्थानीय मध्यस्थ महिला की खाते तक पहुंच को नियंत्रित करते हैं।

3.7 सामाजिक मानदंड और लैंगिक असमानता

OECD का सामाजिक संस्थान और लैंगिक सूचकांक बताता है कि लैंगिक असमानता महिलाओं के अधिकारों और संसाधनों तक पहुंच को सीमित करने वाले सामाजिक मानदंडों और व्यवहारों से भी पैदा होती है (OECD, 2023)। इसलिए लाइली बहना योजना का प्रभाव अध्ययन करते समय, केवल भुगतान-नियमितता का विश्लेषण नहीं करना चाहिए; सामाजिक मानदंड, परिवार की स्वीकृति और सामुदायिक स्तर पर महिला की गतिशीलता भी शामिल होनी चाहिए।

3.8 भारतीय नीति-विमर्श और शोध की आवश्यकता

हाल ही में भारतीय नीति-विमर्श में महिला-केंद्रित नकद अंतरण को गरीबी-निवारण, घरेलू कल्याण और महिला सशक्तिकरण का एक उपकरण माना जाता है। Kumar (2025) का कहना है कि भारत में कई राज्यों ने महिलाओं को लक्षित नकद अंतरण कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिससे घरेलू कल्याण, बचत, आर्थिक फैसले और महिला संस्थाओं पर संभावित प्रभावों पर चर्चा बढ़ी है। फिर भी, राज्य-विशिष्ट, स्थानीय, सामाजिक श्रेणी-आधारित और बैंकिंग व्यवहार-केंद्रित अध्ययनों की जरूरत है।

4. सैद्धांतिक रूपरेखा

4.1 महिला एजेंसी

महिला एजेंसी का अर्थ है महिलाओं की क्षमता जिसके माध्यम से वे अपने जीवन के चुनावों को समझते हैं, निर्णय लेते हैं और संसाधनों पर प्रभावी नियंत्रण रखते हैं। संस्था की औपचारिक उपलब्धता केवल "चयन" नहीं है; यह भी विकल्पों पर अमल करने की सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक क्षमता है। लाइली बहना कार्यक्रम में एजेंसी का मतलब होगा कि महिला पैसे प्राप्त करने, खाते का उपयोग करने, पैसे की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और परिवार में अपनी राय व्यक्त करने में कितनी सक्षम है।

एजेंसी के तीन स्तर हैं: संसाधन तक पहुंच, संसाधन पर नियंत्रण और निर्णय के परिणाम पर प्रभाव। यदि एक महिला पैसे के लिए पति, ससुराल या बैंकिंग मध्यस्थ पर निर्भर रहती है, तो उसके पास पहुंच है लेकिन नियंत्रण है। यदि वह स्वयं निकासी करती है, खर्च निर्धारित करती है और बचत कर सकती है, तो एजेंसी का स्तर उँचा माना जाएगा।

4.2 क्षमता दृष्टिकोण

क्षमता दृष्टिकोण आय में वृद्धि की जगह वास्तविक जीवन में उपलब्धियों में वृद्धि को मानता है (सेन, 1999)। इस दृष्टिकोण से, लाइली बहना योजना का मूल्यांकन केवल महिला को दी गई धनराशि पर नहीं होना चाहिए; इसके बजाय, इस धनराशि ने महिला को कौन-से वास्तविक अवसर दिए। क्या उसने अपने स्वास्थ्य पर खर्च करना बंद कर दिया? क्या मैं बच्चों की पढ़ाई में योगदान दे सकी? क्या वह अपराध-बोध के बिना अपनी छोटी-सी आवश्यकता पर खर्च कर सकी? क्या वह बचत या ऋण-निर्भरता पर अधिक निर्भर हो गया?

शक्ति दृष्टिकोण भी बताता है कि एक ही राशि अलग-अलग महिलाओं पर अलग-अलग परिणाम दे सकती है। महिलाएं जो संयुक्त परिवार में रहती हैं, परित्यक्ता हैं, ग्रामीण दलित हैं, शहरी शिक्षित हैं, या आदिवासी हैं। इसलिए लाभार्थियों को नीति-विश्लेषण में एक समान समूह मानना पर्याप्त नहीं है।

4.3 घरेलू सौदेबाजी सिद्धांत

घरेलू सौदेबाजी सिद्धांत मानता है कि परिवार में संसाधनों का वितरण केवल प्रेम, परंपरा या आवश्यकता से नहीं प्रभावित होता; सदस्यों की आय, संपत्ति, सामाजिक समर्थन और वैकल्पिक विकल्प भी प्रभावित करते हैं। जब एक महिला नियमित आय-स्रोत या नकद अंतरण रखती है, तो वह घरेलू खर्चों, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा और बचत पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित हो सकती है।

इसी बिंदु पर लाइली बहना योजना का संभावित सौदेबाजी-प्रभाव स्थित है। सौदेबाजी-शक्ति सीमित रहती है यदि परिवार महिला को "घर का सामान्य धन" मानकर सामूहिक खर्च में जोड़ देता है, लेकिन वह निर्णय नहीं लेती। महिला का निर्णय-अधिकार बढ़ता है यदि पैसा उसकी आर्थिक पहचान बनाता है और परिवार उसकी आवश्यकताओं को सुनता है।

4.4 वित्तीय समावेशन और लैंगिक सशक्तिकरण

वित्तीय समावेशन का अर्थ बचत, ऋण, बीमा, डिजिटल भुगतान, वित्तीय साक्षरता और वित्तीय निर्णय-क्षमता से होता है, न सिर्फ बैंक खाते की उपलब्धता। RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक 0 से 100 के पैमाने पर मापा जाता है और पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता को शामिल करता है; मार्च 2025 के लिए यह 67.0 था (Press Information Bureau, 2025)। यह ढाँचा कहता है कि “खाता खुलना” वित्तीय समावेशन की शुरुआत है, न कि पूर्णता।

महिला सशक्तिकरण के लिए वित्तीय समावेशन का मतलब है कि महिलाएं अपने खाते को समझ सकें, पासबुक या मोबाइल संदेश पढ़ सकें या समझा सकें, ATM, बैंक मित्र या कियोस्क का उपयोग कर सकें, बचत रख सकें, छोटे ऋण

या बीमा विकल्पों को समझ सके और वित्तीय धोखाधड़ी से बच सके। लाइली बहना योजना की दीर्घकालिक सफलता इस पर निर्भर करती है कि यह महिलाओं को निष्क्रिय लाभार्थी से सक्रिय वित्तीय नागरिक बना सकती है।

5. शोध-अंतराल

5.1 घरेलू निर्णय-अधिकार और वास्तविक नियंत्रण पर सीमित अध्ययन

लाइली बहना योजना पर सार्वजनिक बहस में अक्सर भुगतान राशि, योग्यता, राजनीतिक लोकप्रियता और व्यय पर चर्चा होती है। अकादमिक विश्लेषण, हालांकि, घरेलू निर्णय-अधिकार, बैंक खाते पर वास्तविक नियंत्रण और सामाजिक-आर्थिक स्वायत्तता जैसे गहरे विषयों पर सीमित है।

5.2 लाभार्थी समूहों की अंतर्विभाजित विविधता

दूसरा अंतर यह है कि अधिकांश चर्चा में महिलाओं को एक समान लाभार्थी समूह के रूप में देखा जाता है। योजना का प्रभाव जाति, वर्ग, जाति, ग्रामीण-शहरी स्थिति, वैवाहिक स्थिति, आयु और परिवार संरचना पर निर्भर करता है। वित्तीय समावेशन की परिभाषा में तीसरा अंतर है: योजना में बैंक खाता आवश्यक होने के बावजूद, यह प्रश्न एक अलग अध्ययन की मांग करता है कि क्या महिला स्वयं खाता का उपयोग करती है या परिवार या एजेंट इस प्रक्रिया पर नियंत्रण रखते हैं।

5.3 अंतरण नियमितता और मनोवैज्ञानिक प्रभाव

चौथा अध्ययन नकद अंतरण की नियमितता और मनोवैज्ञानिक प्रभाव से संबंधित है। नियमित और पूर्वानुमेय धनराशि एक महिला को आर्थिक आत्मविश्वास दे सकती है, लेकिन बैंकिंग कठिनाई या अनियमितता इस विश्वास को कम कर सकती है। इसलिए योजना के प्रभाव को मापने के लिए केवल लाभ-प्राप्ति नहीं, बल्कि उपयोग, नियंत्रण, नियमितता, निर्णय-प्रभाव और सामाजिक स्वीकृति भी शामिल होना चाहिए।

6. शोध का लक्ष्य

6.1 मुख्य उद्देश्य

लाइली बहना योजना में प्रत्यक्ष नकद अंतरण और महिला संस्थाओं के संबंध का विश्लेषण करना।

6.2 विशिष्ट उद्देश्य

- यह समझना कि योजना महिला लाभार्थियों के डिजिटल भुगतान, बचत, बैंक खाते का उपयोग और वित्तीय साक्षरता को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है।



- घरेलू निर्णय-अधिकार में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण करना, खाद्य पदार्थों, स्वास्थ्य सेवाओं, बच्चों की शिक्षा, घरेलू खर्चों, बचत और व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर।
- शहरी और ग्रामीण लाभार्थियों के अनुभवों की तुलना करना
- जाति, वर्ग, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, आय और आर्थिक स्थिति पर आधारित योजना के संभावित प्रभावों का विश्लेषण करना
- योजना के कार्यान्वयन में सामाजिक मानदंडों, परिवार द्वारा नियंत्रण, डिजिटल विभाजन, दस्तावेजीकरण और बैंकिंग बाधाओं को समझना।
- महिला सशक्तिकरण को आर्थिक सहायता से आगे बढ़ाने के लिए नीतिगत सुझाव देना

7. शोध प्रश्न

7.1 केंद्रीय शोध प्रश्न

क्या लाइली बहना योजना से प्राप्त नकद अंतरण महिलाओं के घरेलू निर्णय अधिकार को बढ़ाता है?

7.2 सहायक शोध प्रश्न

- क्या स्वयं के DBT-सक्रिय बैंक खाते में भुगतान वास्तव में महिलाओं के वित्तीय समावेशन को बढ़ाता है?
- क्या महिला का योजना राशि पर नियंत्रण सामाजिक-आर्थिक स्वायत्तता और आर्थिक आत्मविश्वास से संबंधित है?
- शहरी और ग्रामीण लाभार्थियों के अनुभवों में कौन-से अंतर हैं?
- शिक्षा, जाति, आय और वैवाहिक स्थिति योजना पर किस प्रकार प्रभाव डालती हैं?
- योजना का सशक्तीकरण-प्रभाव बढ़ाने के लिए कौन-से अतिरिक्त हस्तक्षेप आवश्यक हैं?

8. कल्पनाएँ

8.1 H1: घरेलू निर्णय-अधिकार पर नकद अंतरण का प्रभाव

महिलाओं के घरेलू निर्णय अधिकार पर लाइली बहना योजना से प्राप्त नकद अंतरण का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

8.2 H2: वित्तीय समावेशन पर नियमित अंतरण का प्रभाव

नियमित नकद हस्तांतरण महिलाओं को वित्तीय रूप से समावेशित करता है।

8.3 H3: बैंक खाता नियंत्रण और सामाजिक-आर्थिक स्वतंत्रता

महिलाओं का बैंक खाता पर असली नियंत्रण उनकी सामाजिक-आर्थिक स्वतंत्रता से सकारात्मक रूप से संबंधित है।

8.4 H4: शिक्षा और वित्तीय निर्णय-क्षमता

शिक्षित महिला लाभार्थियों में अधिक वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता होती है।

8.5 H5: ग्रामीण-शहरी प्रभाव-अंतर

शहरी और ग्रामीण लाभार्थियों पर योजना के प्रभाव में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर है।

9. शोध प्रक्रिया

9.1 शोध पद्धति का समग्र स्वरूप

इस शोध पत्र में मात्रात्मक सर्वेक्षण और गुणात्मक साक्षात्कार दोनों का उपयोग किया गया है। इस दस्तावेज़ में वास्तविक प्राथमिक डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्रक्रिया को ऐसा बनाया गया है कि भविष्य में इसे क्षेत्रीय अध्ययन के रूप में उपयोग किया जा सके। उदाहरणात्मक डेटा का उद्देश्य विश्लेषण की संभावित दिशा बताना है, जो प्रस्तुत सांख्यिकीय खंड का आधार है।

9.2 अध्ययन डिजाइन

अध्ययन डिजाइन का प्रस्ताव वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक है। परीक्षण में लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, योजना राशि का उपयोग, वित्तीय व्यवहार, घरेलू निर्णय-अधिकार और स्वायत्तता सूचकांक मापा जाएगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समान नीति के परिणामों को समझने का प्रयास किया जाएगा।

9.3 अध्ययन क्षेत्र

इस अध्ययन में मध्य प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। वास्तविक क्षेत्र अध्ययन में सामाजिक-आर्थिक विविधता के आधार पर मालवा, बुंदेलखंड, महाकौशल, निमाड़ और मध्य क्षेत्र के जिलों को चुना जा दशरथ प्रसाद अहिरवार, विनीता अहिरवार, डॉ पदम् नारायण



सकता है। इस शोध-पत्र में अध्ययन क्षेत्र का परिचय पद्धतिगत रूपरेखा में दिया गया है, न कि वास्तविक सर्वेक्षण-स्थल।

9.4 प्रस्तावित नमूना चयन

प्रस्तावित नमूना बहु-स्तरीय स्तरीकृत चयन पर आधारित होगा और प्रतिभागी पहले स्तर पर जिले, फिर ग्राम पंचायतों या वार्डों और फिर पात्र लाभार्थी महिलाएं चुनी जाएंगी। उदाहरणात्मक विश्लेषण में 240 लाभार्थियों का एक काल्पनिक नमूना लिया गया है, जिसमें 120 लाभार्थी शहरी और 120 ग्रामीण मानकर गणना की गई है।

9.5 डेटा संग्रह उपकरण

प्राथमिक डेटा के लिए, डेटा संग्रह उपकरण संरचित प्रश्नावली, अर्द्ध-संरचित साक्षात्कार और छोटे समूह-चर्चा का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल, बैंकिंग उपयोग, योजना राशि पर नियंत्रण, घरेलू निर्णय अधिकार, डिजिटल वित्तीय साक्षरता, गतिशीलता और आत्मविश्वास के मापदंड प्रश्नावली में शामिल होंगे।

9.6 प्रश्नावली/साक्षात्कार प्रणाली

व्यक्तिगत जानकारी: आयु, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, आकार, आय और सामाजिक श्रेणी

- कार्यक्रम-संबंधी विवरण: पंजीकरण, भुगतान की नियमितता, राशि की जानकारी और बैंकिंग ज्ञान
- धन समावेशन: उपयोग, निकासी, बचत, डिजिटल भुगतान, बीमा और ऋण की जानकारी
- घरेलू फैसले: भोजन, स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, घरेलू खर्च, बचत और व्यक्तिगत व्यय
- स्वतंत्रता और संस्था: गतिशीलता, आत्मविश्वास, परिवार में बोलने की क्षमता और सामुदायिक भागीदारी
- कार्यान्वयन में व्यवधान: दस्तावेज़, परिवार द्वारा धन नियंत्रण, कियोस्क शुल्क, OTP/मोबाइल समस्या, e-KYC और बैंक दूरी

9.7 चर निर्धारण

तालिका 2: प्रस्तावित शोध डिजाइन और चर-रूपरेखा

घटक	विवरण
स्वतंत्र चर	अंतरण की नियमितता, भुगतान की जानकारी, बैंक खाते पर नियंत्रण, शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, परिवार समर्थन

घटक	विवरण
निर्भर चर	महिला एजेंसी सूचकांक, वित्तीय स्वायत्तता सूचकांक, घरेलू निर्णय-अधिकार सूचकांक, आर्थिक आत्मविश्वास
नियंत्रण चर	आयु, जाति/समुदाय, आय-वर्ग, वैवाहिक स्थिति, ग्रामीण-शहरी निवास, परिवार आकार
मापन पैमाना	अधिकांश मनो-सामाजिक संकेतकों के लिए 1 से 5 लिंकट पैमाना; कुछ चर द्विविकल्पी या प्रतिशतात्मक

टिप्पणी: यह पद्धतिगत रूपरेखा भविष्य के फील्ड अध्ययन के लिए प्रस्तावित है।

9.8 सांख्यिकीय विश्लेषण विधियाँ

मात्रात्मक डेटा के लिए वर्णनात्मक आँकड़े, प्रतिशत विश्लेषण, माध्य स्कोर, ग्रामीण-शहरी तुलना, Pearson सहसंबंध, t-परीक्षण/ANOVA और बहुविकल्पी प्रतिगमन विश्लेषण का उपयोग किया जा सकता है। गुणात्मक डेटा का विषय-वस्तु विश्लेषण किया जाएगा, जिसमें “राशि पर नियंत्रण”, “परिवार में आवाज़”, “बैंकिंग बाधा”, “डिजिटल निर्भरता” और “आत्मसम्मान” जैसे कोड विकसित किए जा सकते हैं।

10. डेटा विश्लेषण और परिणाम

इस खंड में प्रस्तुत सभी तालिकाएँ, चार्ट, सहसंबंध और प्रतिगमन परिणाम उदाहरणात्मक/काल्पनिक डेटा पर आधारित हैं। इनका उद्देश्य यह दिखाना है कि वास्तविक फील्ड सर्वेक्षण प्राप्त होने पर लाइली बहना योजना के प्रभाव का विश्लेषण किस प्रकार किया जा सकता है। यहाँ दिए गए परिणामों को आधिकारिक या वास्तविक प्रभाव-आकलन नहीं माना जाना चाहिए।

10.1 लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल

तालिका 3: लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल (उदाहरणात्मक डेटा, n=240)

चर	श्रेणी	संख्या	प्रतिशत
निवास	ग्रामीण	120	50.0
निवास	शहरी	120	50.0
आयु	21-30 वर्ष	68	28.3
आयु	31-40 वर्ष	88	36.7

चर	श्रेणी	संख्या	प्रतिशत
आयु	41-50 वर्ष	59	24.6
आयु	51-59 वर्ष	25	10.4
शिक्षा	औपचारिक शिक्षा नहीं	40	16.7
शिक्षा	प्राथमिक	56	23.3
शिक्षा	माध्यमिक/उच्च माध्यमिक	92	38.3
शिक्षा	स्नातक या अधिक	52	21.7
सामाजिक श्रेणी	अनुसूचित जाति	56	23.3
सामाजिक श्रेणी	अनुसूचित जनजाति	44	18.3
सामाजिक श्रेणी	अन्य पिछड़ा वर्ग	96	40.0
सामाजिक श्रेणी	सामान्य	44	18.4
मासिक पारिवारिक आय	7000 रुपये से कम	54	22.5
मासिक पारिवारिक आय	7001-12000 रुपये	100	41.7
मासिक पारिवारिक आय	12001-20000 रुपये	66	27.5
मासिक पारिवारिक आय	20000 रुपये से अधिक	20	8.3

स्रोत: लेखक द्वारा तैयार उदाहरणात्मक/काल्पनिक डेटा; वास्तविक फील्ड सर्वेक्षण का प्रतिनिधित्व नहीं करता।

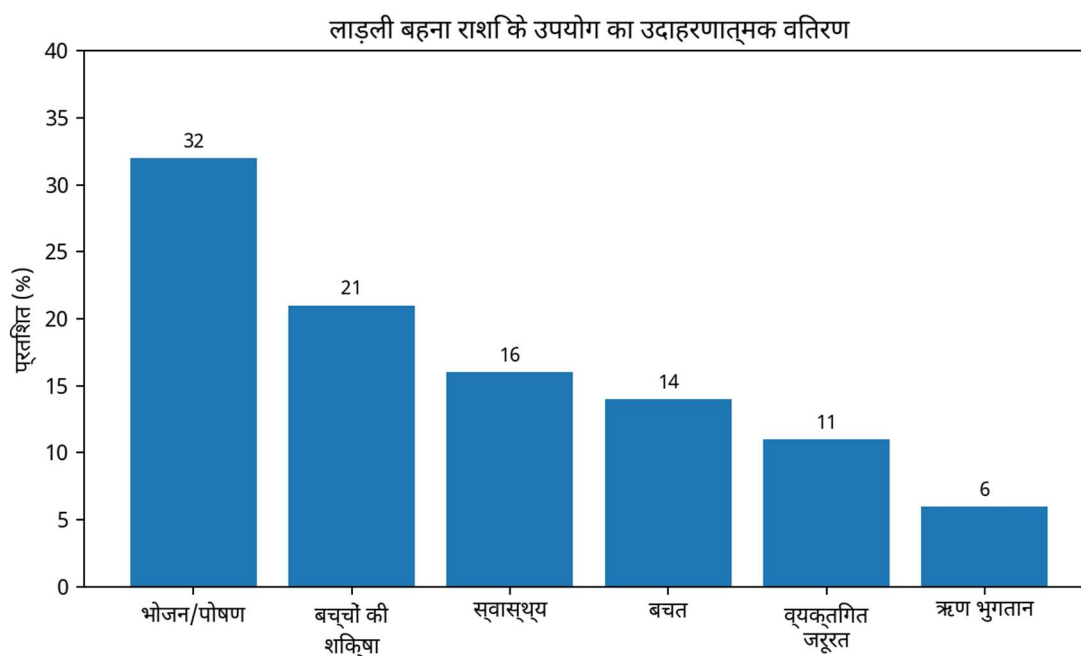
उदाहरणात्मक प्रोफाइल में नमूना ग्रामीण और शहरी लाभार्थियों में समान रूप से विभाजित है। आय और शिक्षा की विविधता यह दिखाने के लिए रखी गई है कि योजना का प्रभाव लाभार्थी के सामाजिक-आर्थिक स्थान के अनुसार बदल सकता है। वास्तविक अध्ययन में यह देखना आवश्यक होगा कि निम्न आय-वर्ग और कम शिक्षा वाली महिलाओं के लिए बैंकिंग प्रक्रिया कितनी सुगम है।

10.2 योजना राशि के उपयोग का विश्लेषण

तालिका 4: योजना राशि के प्रमुख उपयोग (उदाहरणात्मक डेटा)

उपयोग श्रेणी	संख्या	प्रतिशत
भोजन और पोषण संबंधी खर्च	77	32.0
बच्चों की शिक्षा	50	21.0
स्वास्थ्य और दवा	38	16.0
बचत	34	14.0
व्यक्तिगत आवश्यकताएँ	26	11.0
ऋण/उधार भुगतान	15	6.0

टिप्पणी: यह वितरण काल्पनिक है और केवल विश्लेषण-प्रदर्शन के लिए दिया गया है।



चित्र 1: योजना राशि के उपयोग का उदाहरणात्मक वितरण

उदाहरणात्मक परिणामों में भोजन-पोषण, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य खर्च प्रमुख उपयोग-क्षेत्र के रूप में सामने आते हैं। यह पैटर्न उस व्यापक साहित्य से मेल खाता है जिसमें महिला-केंद्रित अंतरणों को घरेलू कल्याण-व्यय से जोड़ा गया है, यद्यपि वास्तविक प्रभाव का निर्धारण फील्ड डेटा से ही किया जा सकता है। बचत का 14 प्रतिशत

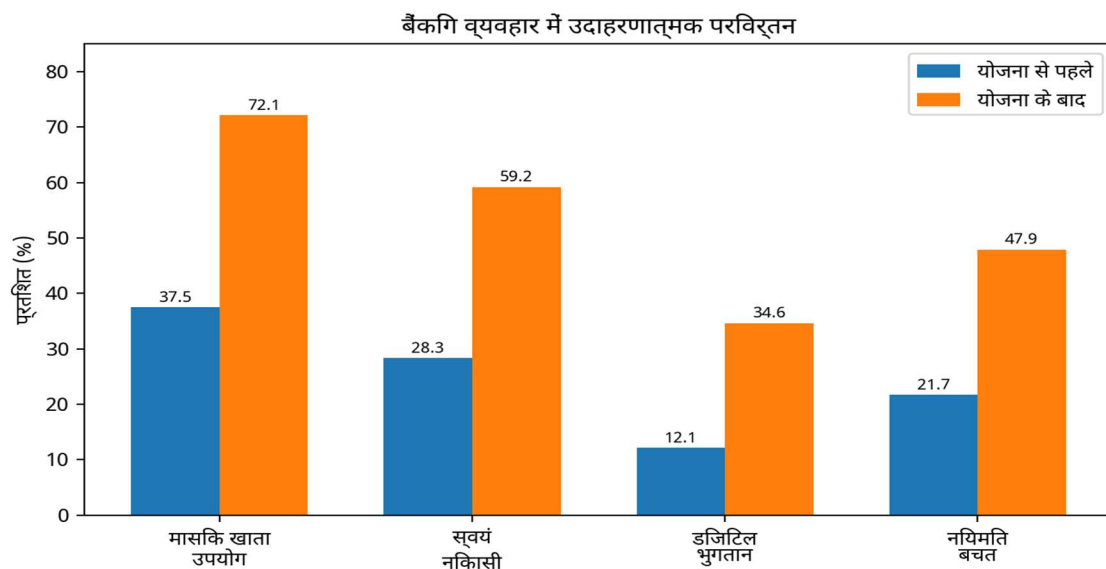
काल्पनिक मान यह संकेत देता है कि नियमित नकद प्रवाह महिला को छोटी बचत की संभावना दे सकता है, पर बचत की क्षमता घरेलू आय-असुरक्षा पर निर्भर रहेगी।

10.3 बैंक खाते के उपयोग में परिवर्तन

तालिका 5: बैंकिंग व्यवहार में परिवर्तन (उदाहरणात्मक डेटा)

संकेतक	योजना से पहले (%)	योजना के बाद (%)	परिवर्तन (प्रतिशत अंक)
मासिक रूप से बैंक खाते का उपयोग	37.5	72.1	+34.6
स्वयं बैंक/कियोस्क से निकासी	28.3	59.2	+30.9
डिजिटल भुगतान का उपयोग	12.1	34.6	+22.5
नियमित छोटी बचत	21.7	47.9	+26.2

स्रोत: लेखक द्वारा तैयार उदाहरणात्मक/काल्पनिक डेटा।



चित्र 2: बैंकिंग व्यवहार में उदाहरणात्मक परिवर्तन

बैंकिंग उपयोग में सबसे अधिक वृद्धि मासिक खाता उपयोग और स्वयं निकासी में दिखाई गई है। यह इस धारणा को स्पष्ट करता है कि नियमित DBT भुगतान खाता-धारिता को सक्रिय उपयोग में बदल सकता है। पर डिजिटल दशरथ प्रसाद अहिरवार, विनीता अहिरवार, डॉ पदम् नारायण

भुगतान का स्तर अपेक्षाकृत कम रहना डिजिटल साक्षरता, मोबाइल स्वामित्व, OTP निर्भरता और स्थानीय डिजिटल अवसंरचना की सीमाओं की ओर संकेत करता है।

10.4 घरेलू निर्णय-अधिकार में परिवर्तन

तालिका 6: घरेलू निर्णय-अधिकार का औसत स्कोर (1=बहुत कम, 5=बहुत अधिक)

निर्णय क्षेत्र	योजना से पहले	योजना के बाद	औसत परिवर्तन
भोजन/राशन संबंधी निर्णय	3.14	3.78	+0.64
स्वास्थ्य उपचार	2.84	3.55	+0.71
बच्चों की शिक्षा	2.77	3.64	+0.87
घरेलू खर्च प्राथमिकता	2.69	3.61	+0.92
बचत/उधार निर्णय	2.31	3.26	+0.95
व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर खर्च	2.42	3.28	+0.86

टिप्पणी: तालिका में प्रस्तुत स्कोर उदाहरणात्मक/काल्पनिक हैं।

उदाहरणात्मक स्कोर बताते हैं कि नकद अंतरण का सबसे स्पष्ट प्रभाव घरेलू खर्च प्राथमिकता, बचत/उधार निर्णय और बच्चों की शिक्षा से जुड़े निर्णयों में दिखाया जा सकता है। यह समझना आवश्यक है कि वास्तविक जीवन में निर्णय-अधिकार अक्सर साझा या बातचीत-आधारित होता है। इसलिए महिला से यह पूछना पर्याप्त नहीं कि “कौन निर्णय लेता है”; यह भी पूछना होगा कि क्या उसकी राय को अंतिम निर्णय में महत्व मिलता है।

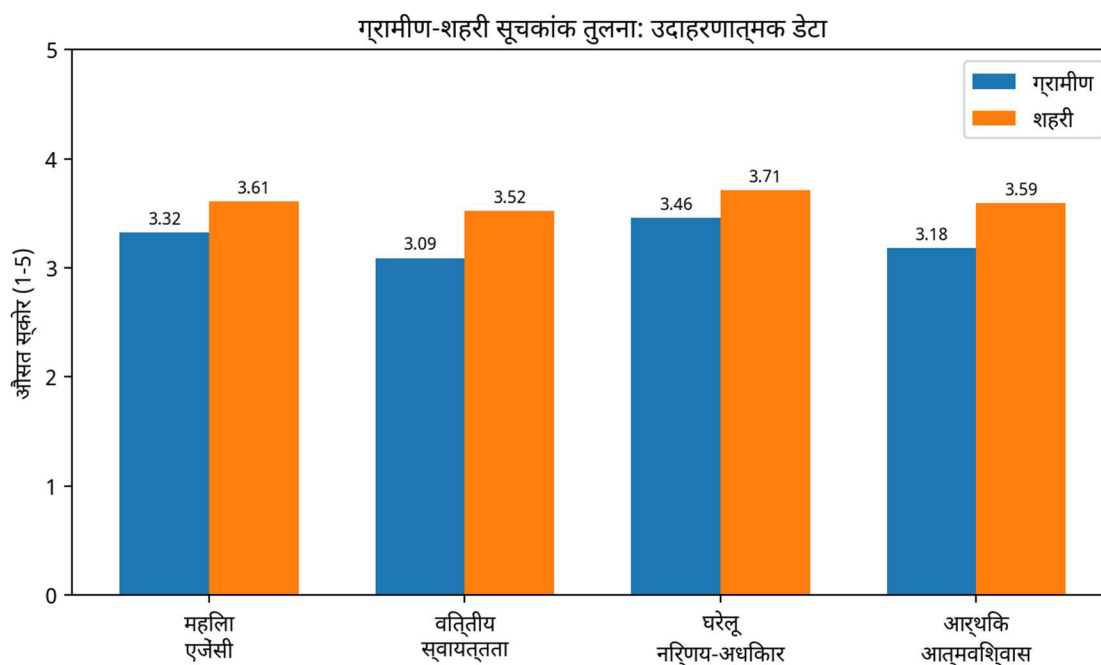
10.5 वित्तीय स्वायत्तता और महिला एजेंसी सूचकांक

तालिका 7: ग्रामीण-शहरी सूचकांक तुलना (उदाहरणात्मक औसत स्कोर)

सूचकांक	ग्रामीण	शहरी	अंतर
महिला एजेंसी सूचकांक	3.32	3.61	+0.29
वित्तीय स्वायत्तता सूचकांक	3.09	3.52	+0.43
घरेलू निर्णय-अधिकार	3.46	3.71	+0.25

सूचकांक	ग्रामीण	शहरी	अंतर
सूचकांक			
आर्थिक आत्मविश्वास सूचकांक	3.18	3.59	+0.41

स्रोत: लेखक द्वारा तैयार उदाहरणात्मक/काल्पनिक डेटा; स्कोर 1 से 5 पैमाने पर आधारित है।



चित्र 3: ग्रामीण-शहरी सूचकांक तुलना

उदाहरणात्मक तुलना में शहरी लाभार्थियों के स्कोर सभी सूचकांकों पर ग्रामीण लाभार्थियों से अधिक दिखाए गए हैं। यह अंतर बैंकिंग दूरी, मोबाइल उपयोग, डिजिटल भुगतान, परिवहन और सेवा-संपर्क में ग्रामीण-शहरी असमानताओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता बताता है। हालांकि ग्रामीण महिलाओं के लिए छोटी नियमित राशि का महत्व अधिक हो सकता है, लेकिन उसका उपयोग-संरचना स्थानीय अवसंरचना से प्रभावित होगी।

10.6 सहसंबंध विश्लेषण

तालिका 8: चयनित चरों का Pearson सहसंबंध मैट्रिक्स (उदाहरणात्मक डेटा)

चर	नियमितता	खाता नियंत्रण	वित्तीय स्वायत्तता	महिला एजेंसी	आर्थिक आत्मविश्वास
अंतरण	1.00	0.42**	0.38**	0.44**	0.40**

चर	नियमितता	खाता नियंत्रण	वित्तीय स्वायत्तता	महिला एजेंसी	आर्थिक आत्मविश्वास
नियमितता					
बैंक खाते पर नियंत्रण	0.42**	1.00	0.56**	0.51**	0.49**
वित्तीय स्वायत्तता सूचकांक	0.38**	0.56**	1.00	0.62**	0.58**
महिला एजेंसी सूचकांक	0.44**	0.51**	0.62**	1.00	0.61**
आर्थिक आत्मविश्वास	0.40**	0.49**	0.58**	0.61**	1.00

टिप्पणी: ** $p < 0.01$; सभी परिणाम काल्पनिक/उदाहरणात्मक हैं।

सहसंबंध मैट्रिक्स में बैंक खाते पर नियंत्रण का वित्तीय स्वायत्तता और महिला एजेंसी से मध्यम से मजबूत सकारात्मक संबंध दिखाया गया है। इससे यह विश्लेषणात्मक संकेत मिलता है कि योजना राशि का महिला के खाते में आना तभी अधिक प्रभावी होगा जब महिला खाते का वास्तविक उपयोग और नियंत्रण कर सके। अंतरण नियमितता का आर्थिक आत्मविश्वास से सकारात्मक संबंध भी यह बताता है कि भुगतान की पूर्वानुमेयता महिला के मनोवैज्ञानिक सुरक्षा-बोध को प्रभावित कर सकती है।

10.7 प्रतिगमन विश्लेषण

तालिका 9: सामाजिक-आर्थिक स्वायत्तता सूचकांक पर बहुविकल्पी प्रतिगमन (उदाहरणात्मक डेटा)

स्वतंत्र चर	B	मानकीकृत बीटा	t	p-मूल्य
स्थिरांक	1.22	-	5.11	0.000
बैंक खाते पर नियंत्रण	0.31	0.29	4.82	0.000
अंतरण की नियमितता	0.28	0.24	3.91	0.001
शिक्षा स्तर	0.18	0.16	2.54	0.012

स्वतंत्र चर	B	मानकीकृत बीटा	t	p-मूल्य
शहरी निवास	0.14	0.12	2.13	0.034
परिवार का समर्थन	0.22	0.21	3.04	0.003
डिजिटल साक्षरता	0.20	0.18	2.78	0.006

निर्भर चर: सामाजिक-आर्थिक स्वायत्तता सूचकांक; $n=240$; $R^2=0.46$, समायोजित $R^2=0.44$, $F=32.10$, $p<0.001$ / परिणाम काल्पनिक/उदाहरणात्मक हैं।

प्रतिगमन मॉडल में बैंक खाते पर नियंत्रण, अंतरण की नियमितता, पारिवारिक समर्थन और डिजिटल साक्षरता को स्वायत्तता के प्रमुख भविष्यवक्ता के रूप में दिखाया गया है। इस उदाहरणात्मक मॉडल का मूल निष्कर्ष यह है कि नकद अंतरण का प्रभाव अकेले भुगतान से नहीं, बल्कि वित्तीय नियंत्रण, व्यावहारिक क्षमता और घरेलू सामाजिक स्वीकृति से निर्मित होता है।

10.8 परिकल्पना परीक्षण

तालिका 10: परिकल्पना परीक्षण का सारांश (उदाहरणात्मक डेटा)

परिकल्पना	कथन	प्रमुख संकेत	स्थिति
H1	नकद अंतरण का घरेलू निर्णय-अधिकार पर सकारात्मक प्रभाव	औसत स्कोर में वृद्धि	समर्थित
H2	नियमित अंतरण वित्तीय समावेशन बढ़ाता है	बैंकिंग उपयोग संकेतकों में वृद्धि	समर्थित
H3	बैंक खाते पर नियंत्रण स्वायत्तता से सकारात्मक संबंधित है	$r=0.56$, $p<0.01$	समर्थित
H4	शिक्षित महिलाओं में वित्तीय निर्णय क्षमता अधिक	प्रतिगमन में शिक्षा सकारात्मक	समर्थित
H5	ग्रामीण-शहरी प्रभाव में अंतर	शहरी स्कोर अधिक	आंशिक रूप से समर्थित

टिप्पणी: सभी सांख्यिकीय संकेत काल्पनिक/उदाहरणात्मक हैं। वास्तविक निष्कर्ष के लिए प्राथमिक फील्ड डेटा आवश्यक होगा।

11. चर्चा

11.1 नकद अंतरण से निर्णय-अधिकार तक

लाइली बहना योजना का विश्लेषण बताता है कि महिला-केंद्रित नकद अंतरण तीन स्तरों पर होता है: तत्काल आय-सहायता, वित्तीय प्रणाली से संपर्क और घरेलू निर्णय-स्थल में महिला की भूमिका DBT-सक्रिय स्वयं के खाते योजना का जोर इस बात पर है कि महिला को संसाधन की प्रत्यक्ष प्राप्तकर्ता बनाना सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन नियंत्रण और प्राप्ति के बीच की सामाजिक दूरी को नीतिगत रूप से हल करना चाहिए।

11.2 वित्तीय नियंत्रण और डिजिटल निर्भरता

महिला एजेंसी बनाना एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है। खाते में पैसे आने के बाद भी, यदि वह अकेले बैंक नहीं जा सकती, उसका मोबाइल पति के पास रहता है, OTP पढ़ना मुश्किल है या कियोस्क एजेंट पर बहुत निर्भर है, तो उसका स्वतंत्र उपयोग सीमित हो जाता है। इसलिए वित्तीय समावेशन को बैंक खाते से नहीं, बल्कि खाते का उपयोग और महिला की समझ से मापना चाहिए। Global Findex के भारत के परिणाम भी खाता-स्वामित्व और डिजिटल भुगतान का उपयोग के बीच अंतर को दिखाते हैं (Klapper, 2022)।

11.3 NFHS संकेतक और डिजिटल अंतर

NFHS-5 में मध्य प्रदेश की 74.7 प्रतिशत महिलाओं द्वारा स्वयं उपयोग किए जाने वाले बैंक और बचत खाते का संकेतक इस योजना को बल देता है (IIPS & ICF, 2021)। यही डेटा बताता है कि मोबाइल फोन का स्वयं उपयोग 38.5% है, जो डिजिटल भुगतान और SMS/OTP-आधारित बैंकिंग से लैंगिक डिजिटल अंतर को दिखाता है। इसका अर्थ है कि डिजिटल साक्षरता, मोबाइल स्वामित्व और सुरक्षित निकासी को बैंक खाते में पैसे जमा करने से जोड़ना चाहिए।

11.4 घरेलू उपयोग और सशक्तिकरण की सीमा

योजना राशि का घरेलू उपयोग भी सामाजिक है। यदि महिला भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर इस राशि खर्च करती है, तो यह परिवार की सुरक्षा में योगदान देता है। नीति-मूल्यांकन में यह भी देखना चाहिए कि क्या उसे उद्यमिता, बचत या व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर खर्च करने की अनुमति मिलती है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ सिर्फ "घर पर खर्च" नहीं होगा, क्योंकि इससे उनकी भूमिका पुनः देखभालकर्ता तक सीमित हो सकती है।

11.5 ग्रामीण-शहरी अंतर

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मित्र, कियोस्क, परिवहन और नेटवर्क पर अधिक निर्भरता होती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग पहुंच, डिजिटल भुगतान और जानकारी की उपलब्धता अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न आय वाले परिवारों में छोटी नियमित राशि की उपयोगिता अधिक हो सकती है। इसलिए परिणामों और प्रक्रियाओं दोनों को योजना का मूल्यांकन करना चाहिए।

11.6 जाति, वर्ग और वैवाहिक स्थिति की भूमिका

जाति, वर्ग और वैवाहिक स्थिति योजना पर काफी प्रभाव डाल सकते हैं। विवाहित महिलाओं के लिए धन का नियंत्रण अधिक बातचीत-आधारित हो सकता है, लेकिन विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए यह एक व्यक्तिगत सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकता है। अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों में दस्तावेजीकरण और बैंक दूरी की समस्याएं अधिक खतरनाक हो सकती हैं।

11.7 दीर्घकालिक सशक्तिकरण की शर्तें

योजना की एक महत्वपूर्ण सीमा यह है कि नकद अंतरण स्वयं देखभाल कार्य, रोजगार या संपत्ति अधिकार की वापसी नहीं सुनिश्चित करता। यह महिला को न्यूनतम आर्थिक आधार देता है, लेकिन दीर्घकालिक सशक्तिकरण के लिए कौशल-विकास, स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म उद्यम, वित्तीय परामर्श, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ और सुरक्षित सार्वजनिक संरचना आवश्यक हैं।

12. मुख्य निष्कर्ष

12.1 प्रत्यक्ष आर्थिक प्राप्तकर्ता के रूप में महिला

DBT-सक्रिय स्वयं के बैंक खाते में भुगतान वाला डिज़ाइन लाइली बहना योजना में एक महिला को प्रत्यक्ष आर्थिक प्राप्तकर्ता बनाता है।

12.2 योजना के प्रभाव से जुड़े संक्षिप्त निष्कर्ष

- योजना महिला के घरेलू निर्णय-अधिकार को बढ़ा सकती है, लेकिन वास्तविक नियंत्रण परिवार में महिला की आवाज़ और धन पर निर्भर करता है।
- बैंक खाते की उपलब्धता नहीं, बल्कि खाते का सक्रिय उपयोग, बचत, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समझ का अर्थ है।



- ग्रामीण महिलाओं के लिए बैंकिंग की दूरी, कियोस्क पर निर्भरता, मोबाइल उपलब्धता और डिजिटल साक्षरता महत्वपूर्ण बाधाएँ हो सकती हैं।
- शहरी लाभार्थियों में बैंकिंग और डिजिटल उपकरण का उपयोग करने की अधिक संभावना हो सकती है, लेकिन शहरी गरीब महिलाओं के लिए भी आय-अस्थिरता और परिवार नियंत्रण महत्वपूर्ण मुद्दे रह सकते हैं।
- योजना का प्रभाव जाति, आय-वर्ग, शिक्षा और वैवाहिक स्थिति पर निर्भर करता है; इसलिए, समान नीति-निष्कर्ष काफी नहीं हैं।
- वित्तीय साक्षरता, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और सामुदायिक समर्थन के बिना महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता।

13. नीतिगत सुझाव

13.1 वित्तीय साक्षरता शिविर

प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड में लाभार्थी महिलाओं को पासबुक पढ़ने, डिजिटल धोखाधड़ी (DBT) प्रक्रियाओं की जांच करने, सुरक्षित निकासी, ATM और कियोस्क का उपयोग करने और डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव पर नियमित प्रशिक्षण दिया जाए।

13.2 महिलाओं के लिए बैंकिंग सहायता

ताकि लाभार्थी आसानी से सहायता पा सकें, बैंक मित्र और कियोस्क सेवाओं में महिला सुविधा दिवस या महिला सहायक की व्यवस्था की जाए।

13.3 खाते पर वास्तविक नियंत्रण की निगरानी

DBT ही सफलता का पर्याप्त संकेत नहीं है; यह भी मापा जाए कि निकासी कौन करता है, राशि पर निर्णय कौन लेता है और महिला को भुगतान संदेश मिलता है या नहीं।

13.4 ग्रामीण बैंकिंग और सेवा-अवसंरचना सुधार

ग्रामों में पंचायत-आधारित बैंकिंग कैंप, मोबाइल बैंकिंग वैन और शिकायत-निवारण डेस्क लगाए जाएँ।

13.5 डिजिटल एकीकरण और सुरक्षा

योजना में महिला के मोबाइल उपयोग, SMS पढ़ना/समझना, UPI/AEPS सुरक्षा और हेल्पलाइन जानकारी शामिल करें।

13.6 स्वयं सहायता समूहों के साथ समन्वय

योजना में लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों, सूक्ष्म उद्यम, सामुदायिक बचत कार्यक्रमों और कौशल प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा।

13.7 सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन

समुदाय और परिवार स्तर पर चर्चा करके महिलाओं को बताया जाए कि योजना की राशि उनकी आर्थिक पहचान और निर्णय अधिकार से जुड़ी है।

13.8 सुरक्षित और गोपनीय शिकायत तंत्र

परिवार द्वारा धन नियंत्रण, भुगतान विफलता, अनधिकृत निकासी, कियोस्क कटौती और दस्तावेज़ समस्याओं के लिए एक गोपनीय शिकायत प्रणाली बनाई जाए।

13.9 संवेदनशील लाभार्थी समूहों के लिए लक्षित मदद

विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग, आदिवासी और अति गरीब लाभार्थियों को अधिक हैंडहोल्डिंग और दस्तावेज़ सहायता दी जाए।

13.10 निरंतर स्वतंत्र प्रभाव-परीक्षण

योजना का मूल्यांकन महिला एजेंसी, वित्तीय व्यवहार और घरेलू निर्णय अधिकार से किया जाएगा, नहीं सिर्फ लाभार्थी की संख्या या कुल भुगतान से।

14. सीमाएँ

14.1 प्राथमिक डेटा-संबंधी सीमा

इस अध्ययन में प्रस्तुत सांख्यिकीय नतीजे प्राथमिक सर्वेक्षण की सच्चाई पर आधारित नहीं हैं; इसलिए वे वास्तविक प्रभाव-मूल्यांकन नहीं हो सकते।

14.2 वास्तविक प्रभाव-मूल्यांकन के लिए डेटा की आवश्यकता

योजना का वास्तविक प्रभाव निर्धारित करने के लिए भुगतान रिकॉर्ड, लाभार्थी सर्वेक्षण, गैर-लाभार्थी तुलना समूह और समय-श्रृंखला डेटा की आवश्यकता होगी।

14.3 आत्म-रिपोर्ट आधारित संकेतकों की सीमा

घरेलू निर्णय-अधिकार के संकेतक आत्म-रिपोर्ट पर आधारित हैं, इसलिए सामाजिक वांछनीयता पूर्वाग्रही हो सकती है।

14.4 नीति-व्यय और बजटीय विश्लेषण की सीमा

राजनीतिक लोकप्रियता, राजकोषीय स्थिरता और दीर्घकालिक बजटीय प्रभाव इस शोध-पत्र का मुख्य मुद्दा नहीं हैं, लेकिन ये सब नीति-विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

14.5 उप-समूह विश्लेषण की आवश्यकता

भविष्य के वास्तविक अध्ययन में जाति, आदिवासी क्षेत्र, विकलांगता, एकल महिला और प्रवासी परिवार के अलावा अन्य उप-समूहों का व्यापक विश्लेषण आवश्यक होगा।

15. भविष्य के अध्ययन की संभावनाएँ

15.1 क्षेत्रीय फील्ड सर्वेक्षण की संभावना

योजना के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में वास्तविक क्षेत्र सर्वेक्षण किया जा सकता है।

15.2 लाभार्थी और गैर-लाभार्थी तुलना

योजना के शुद्ध प्रभाव का अनुमान लाभार्थी और गैर-लाभार्थी महिलाओं की तुलना से अधिक बलवान हो सकता है।

15.3 DBT, घरेलू सर्वेक्षण और बैंकिंग डेटा का एकीकरण

DBT भुगतान रिकॉर्ड, घरेलू सर्वेक्षण और बैंकिंग डेटा को जोड़कर वित्तीय व्यवहार में बदलाव का दीर्घकालिक अध्ययन किया जा सकता है।

15.4 गुणात्मक अनुसंधान की संभावनाएँ

गुणात्मक अध्ययन, खासकर परिवार में बातचीत, आत्मसम्मान और सामाजिक गतिशीलता पर, महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकता है।

15.5 स्वयं सहायता समूह और उद्यमिता-आधारित अध्ययन

स्वयं सहायता समूह, कौशल-विकास कार्यक्रम और सूक्ष्म उद्यम कार्यक्रम अध्ययन का नया क्षेत्र हो सकते हैं।

15.6 अंतर-राज्यीय तुलनात्मक अध्ययन

अंतर-राज्यीय तुलना से यह समझा जा सकता है कि महिला-केंद्रित नकद अंतरण कार्यक्रमों का डिजाइन और प्रभाव किस प्रकार अलग-अलग राज्यों में होता है।

16. निष्कर्ष

16.1 योजना का समेकित मूल्यांकन

मध्य प्रदेश की लाइली बहना योजना एक महिला-केंद्रित प्रत्यक्ष नकद अंतरण का उदाहरण है, जिसमें आर्थिक सहायता और महिला निर्णय अधिकार को एक साथ रखने का प्रयास दिखाई देता है। महिला के स्वयं के आधार-लिंग और DBT-सक्रिय खाते में धन की आधिकारिक हस्तांतरण, संस्थान और वित्तीय समावेशन के बीच नीतिगत पुल बनाता है।

16.2 नकद अंतरण की उपयोगिता और सीमाएँ

शोध-पत्र का मुख्य निष्कर्ष है कि नकद अंतरण आवश्यक है, लेकिन अपूर्ण उपाय है। यह महिला को नियमित संसाधन, आर्थिक दृश्यता और घरेलू बातचीत में आधार दे सकता है, लेकिन खाते पर नियंत्रण, वित्तीय साक्षरता, सुरक्षित निकासी, डिजिटल क्षमता, पारिवारिक समर्थन और सामाजिक मानदंडों में बदलाव सामाजिक-आर्थिक स्वायत्तता के लिए आवश्यक हैं।

16.3 निर्णय-अधिकार की ओर नीति-यात्रा

योजना का प्रभाव मुख्यतः खपत-सहायता तक सीमित रह सकता है अगर यह मासिक भुगतान तक सीमित रहता है। यह योजना "नकद अंतरण" से "निर्णय-अधिकार" की ओर बढ़ सकती है अगर इसे वित्तीय साक्षरता, स्वयं सहायता समूह, कौशल विकास, डिजिटल समावेशन और महिला-केंद्रित शिकायत व्यवस्था से जोड़ा गया।

16.4 समापन टिप्पणी

वास्तव में, लाइली बहना योजना का मूल्यांकन पैसे के आकार से नहीं होना चाहिए, बल्कि यह कि क्या महिला अपने जीवन, परिवार और आर्थिक भविष्य के निर्णयों में अधिक सुखे, मान्य और सक्षम हुई है। नकद अंतरण से निर्णय-अधिकार तक की असली नीति-यात्रा यही है।

संदर्भ सूची

Center for Financial Inclusion & World Food Programme. (2023). Sending cash transfers to women: How to design programs that enhance well-being while safeguarding against intimate partner violence. Center for Financial Inclusion. <https://www.centerforfinancialinclusion.org/>

Direct Benefit Transfer Mission. (n.d.). About Direct Benefit Transfer. Government of India. <https://dbtbharat.gov.in/>

Field, E., Pande, R., Rigol, N., Schaner, S., & Troyer Moore, C. (2021). On her own account: How strengthening women's financial control impacts labor supply and gender norms. *American Economic Review*, 111(7), 2342–2375. <https://doi.org/10.1257/aer.20200705>

International Institute for Population Sciences (IIPS) & ICF. (2021). National Family Health Survey (NFHS-5), 2019–21: India and Madhya Pradesh fact sheet. IIPS. <https://www.nfhsiips.in/>

Klapper, L. (2022). The Global Findex Database 2021: India country brief. World Bank. <https://thedocs.worldbank.org/>

Kumar, S. (2025). Cash transfers as an instrument for poverty alleviation and women's empowerment in India. Observer Research Foundation Issue Brief No. 814. <https://www.orfonline.org/>

मध्य प्रदेश शासन. (n.d.-a). मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना: योजना की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, पात्रता और भुगतान प्रक्रिया. <https://cmladlibahna.mp.gov.in/>

मध्य प्रदेश शासन. (n.d.-b). मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना: सामान्य प्रश्न. <https://cmladlibahna.mp.gov.in/FAQ.aspx>

NITI Aayog. (2023). National Multidimensional Poverty Index: A progress review 2023. Government of India. <https://www.niti.gov.in/>



Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). SIGI 2023 Global Report: Gender equality in times of crisis. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/>

Press Information Bureau. (2025). RBI's Financial Inclusion Index rises to 67 in 2025 indicating growth for everyone. Government of India. <https://www.pib.gov.in/>

Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.

Somville, V., Almås, I., & Vandewalle, L. (2020). Gender-targeted cash transfers and household decision making: Evidence from India. Department of Economics, Norwegian School of Economics, Discussion Paper No. 16/2020. <https://www.nhh.no/>

UNDP India. (2023). National Multidimensional Poverty Index: A progress review 2023. United Nations Development Programme. <https://www.undp.org/india/>

World Bank Group. (2024). World Bank Group Gender Strategy 2024–2030: Implementation plan. World Bank. <https://www.worldbank.org/>

World Bank. (2022). The Global Findex Database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex>